International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-6 Nov-Dec-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति का अवलोकन

डॉ० श्रद्धानंद राय

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति के मुख्य आयामों का विश्लेषण किया गया है। विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों का मुख्य आधार होती है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। इन्हीं राष्ट्रीय होतों को ध्यान में रख कर विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। शीत युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तथा इसके साथ ही भारत की विदेश नीति में भी परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। 2014 में नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते है और इसके साथ ही भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश नीति का निर्माण करते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभारना है। इसके साथ पड़ोसी पहले की नीति को मजबूती से लागू करना, एक्ट ईस्ट नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, भारतीय आत्मनिर्भरता, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना तथा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है।

कुंजी–शब्द: राष्ट्रीय हित, कूटनीति, सांस्कृतिक, चीन – पाकिस्तान, 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'

सामान्यता यह माना जाता की सरकार बदलने पर वैश्विक राष्ट्रों की विदेश नीति में खास परिवर्तन नही होता है। क्योंकि किसी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्धारित एवं क्रियान्वित होती है। विदेश नीति किसी राजनीतिक दल अथवा किसी सरकार की नीति नही होती है अपितु यह एक राष्ट्र का आधार होती है। जिसके द्वारा किसी राष्ट्र को मजबूती मिलती है। परंतु हम देखते हैं की 2014 में वर्षों बाद भारतीय जाता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में आती है। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के मजबूत सरकार के प्रधानमंत्री बनते है और विदेश नीति को प्राभावी रूप से क्रियान्वित करते है। इस समय भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और इस समय क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी कम हो जाती है। भारतीय राजनीतिक सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक मजबूत एवं स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण

किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में विश्व के तमाम देशों की राजकीय यात्राएँ की और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वैशिवक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका अदा किया है (एंड्रयू 2015)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दिशा है। वैश्विक राजनीति में भारत को एक शक्ति के रूप में उभारने का काम मोदी सरकार की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति को निम्नलिखित आयामों द्वारा समझा जा सकता है।

'पड़ोसी पहले की नीति' (Neighbourhood First Policy)

भारत अपनी विदेश नीति में शुरू से ही पड़ोसियों को मुख्य रूप से अहमियत देता रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ एक ओर जहाँ अफगानिस्तान, बांग्लादेश व श्रीलंका के साथ आर्थिक व सामरिक रिश्ते मजबूत किए। वहीं नेपाल जैसे पड़ोसी देश के साथ रोटी व बेटी का रिश्ता भी निभाता रहा है। संबंधो में मधुरता व खटास समय के अनुसार बदलतर रहते हैं परंतु पड़ोसी बदले नही जा सकते हैं। पड़ोसी पहले नीति की मोदी सरकार के विदेश नीति की मुख्य स्तम्भ माना जा सकता है। इसके द्वारा मोदी सरकार ने गुजराल सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू करने पर बल दिया। इस प्रकार पड़ोसी पहले की नीति के द्वारा मोदी सरकार ने यह जताने का प्रयास किया कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एक बेहतर, सदभाव पूर्ण व मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करने का हर सम्भव प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी विदेशी नीति के द्वारा अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर व मजबूत आर्थिक, राजनीतिक एंव सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किए गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत ने दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु 'पूर्व की ओर देखो' नीति अपनाई। भारत ने 'गुजराल सिद्धांत' के तहत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधो को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए इस नीति का विदेश नीति का मुख्य आधार बनाया। जिसमें पड़ोसी देशों एकतरफा छूट देने की नीति पर भी कार्य किया जिसे 'फरक्का समझौते' के संदर्भ में समझा जा सकता है। 2014 में वर्तमान मोदी सरकार ने विदेश नीति में निरंतरता के तत्त्वों को बनाए रखने के साथ–साथ वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसे अधिक गतिशील बनाते हुए 'पड़ोसी पहले की नीति' को प्राथमिकता प्रदान की है (गांगुली, सुमित (2016)।

'पड़ोसी पहले की' नीति में भी भारतीय विदेश नीति में विद्यमान निरंतरता के तत्त्वों को कायम रखा गया है, जिसमें वैश्विक शांति, मित्रता एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल प्रदान करते हुए गुजराल सिद्धांत की प्राथमिकता को स्वीकार लिया गया है। इस नीति के द्वारा पड़ोसी देशों के आर्थिक विकास तथा संवृद्धि में भागीदार बनने की प्रतिबद्धता को बल प्रदान किया गया है। इसमें किसी देश के दल–विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी देशों के साथ संबंधों को मधुर एवं प्रगाढ़ बनाने का

प्रयास किया गया है। इसके तहत वर्तमान मोदी सरकार द्वारा पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्रदान करके उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करते हुए इनमें क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा निवेश को आगे बढ़ाया जा रहा है (घोष, पीयू 2017)।

'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy)

'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' पूर्वी देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों को एक नई दिशा देने हेतु मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया है। 'पूर्व की ओर देखो नीति' भारत की विदेश नीति का एक मुख्य आधार मानी जाती रही है। 'पूर्व की ओर देखो नीति' भारत की विदेश नीति में 1990 के बाद अपनाई गयी थी। परंतु इस नीति के द्वारा जहाँ एक तरफ भारतीय विदेश नीति की एक वैश्विक पहचान बनी, वहीं दूसरी तरफ इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में अनेक प्रकार से बाधाएँ बनी रहीं हैं। परंतु मोदी सरकार द्वारा पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने हेतु एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति को अपनाया। यह विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया–प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहल है।

इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन एवं निरंतर जुड़ाव शामिल है। इस नीति के द्वारा आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया–प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है, जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ आर्थिक एकीकरण करने पर बल दिया जा रहा है तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग एंव सुरक्षा पर केंद्रित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के '4C* का उल्लेख किया है। संस्कृति (Culture), वाणिज्य (Commerce), संपर्क (Connectivity), क्षमता निर्माण (Capacity building) । इसके साथ – साथ सुरक्षा भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक मुख्य विशेषता रही है (हैदर, सुहासिनी 2020)।

सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy)

भारत की सांस्कृतिक विरासत प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण रही है। सैंधव सभ्यता के समय से ही भारत के सांस्कृतिक सम्बंध विदेशों से होते रहे हैं। भारत ने अपनी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा के द्वारा विदेशी शासकों को आकृष्ट किया तथा अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया। सांस्कृतिक कूटनीति को मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। सांस्कृतिक कूटनीति का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और मूल्यों को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से रिश्तों को मजबूत करना है। मोदी सरकार ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की। जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में घोषित किया गया और यह भारत की संस्कृति को वैश्विक स्तर एक नयी पहचान मिली।

सॉफ्ट पावर नीति का प्रयोग द्वारा मोदी सरकार ने भारतीय विदेश नीति को सिनेमा, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, और साहित्य के माध्यम से भारत की छवि को मजबूत किया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक कूटनीति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारत ने बौद्ध सर्किट विकसित करने और दुनिया भर के बौद्ध बहुल देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत सरकार ने भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों वाराणसी, अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों का विकास और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कूटनीति किसी देश के विदेश नीति को मजबूत आधार देने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में भारत ने भी अपनी विदेश नीति में सांस्कृतिक कूटनीति को मुख्य आधार बनाया। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने पर सांस्कृतिक कूटनीति को भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत बनाया। यह मोदी सरकार की सांस्कृतिक कूटनीति की एक बड़ी सफलता है जिसने संपूर्ण विश्व को भारत की ओर आकर्षित किया है (गांगुली, सुमित 2018)।

आर्थिक विदेश नीति (Economic Foreign Policy)

किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति में आर्थिक नीति प्रमुख आधार होती है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए एक मजबूत आर्थिक नीति पर बल दिया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा विदेश नीति में अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भारत द्वारा चीन, जापान, अमेरिका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी सरकार की आर्थिक विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को मजबूत करना, और विदेशी निवेश आकर्षित करना रहा है। विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए प्रेरित किया गया है जिससे ये कंपनियाँ भारत में आकर अधिक से अधिक रोजगार व व्यवसाय के अवसर बढा सकें। भारत द्वारा विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है। विभिन्न देशों और क्षेत्रों खास कर दक्षिण पूर्व के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर चर्चा और हस्ताक्षर किए गए हैं । भारत–दक्षिण पूर्वे एशिया के देशों, भारत–यूएई और भारत–जापान जैसे देशों के साथ व्यापार और निवेश को मजबूत किया गया है। भारत द्वारा खाड़ी देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया। भारत रूस, अमेरिका, और फ्रांस जैसे देशों के साथ रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जा रहा है। पड़ोसी देशों (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका) के साथ आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिशें की गईं। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भागीदारी को मजबूत किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स और द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए विदेशी निवेश को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं (हर्ष, वी. पंत (2016)।

भारतीय प्रवासी कूटनीति

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विदेश नीति में भारतीय प्रवासियों के साथ मजबूत सम्बंध बनाकर उन्हें भारत में निवेश हेतु आकर्षित किया जा रहा है। भारतीय मूल के लोगों का विदेशों में रहने वालों की अत्यधिक संख्या है। जो भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरत में भारतीय प्रवासियों को सीधे तौर सम्बोधित किया गया तथा भारत के हितों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय प्रवासी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रवासी भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनीतिक सेतु का कार्य करते हैं। भारत की विदेश नीति में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता है। भारतीय प्रवासी भारत को विदेशी मुद्रा भेजने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रवासी भारतीय भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलती है। प्रवासी भारतीय भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को विदेशों में फैलाने में मदद करते हैं। इसके द्वारा योग, बॉलीवुड, भारतीय भोजन और त्योहारों के प्रचार के माध्यम से वे भारत की 'सॉफ्ट पावर' को बढ़ाते हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय कई देशों में राजनैतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, यूके, और कनाडा। ये समुदाय भारत के हितों को इन देशों की नीतियों में सम्मिलित करने में मदद करते हैं। प्रवासी भारतीय विभिन्न देशों की संसदों और सरकारों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, जो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, जैसे भूकंप और बाढ़, या वैश्विक संकटों (जैसे कोविड–19 महामारी) के दौरान प्रवासी भारतीय धन और सामग्री सहायता प्रदान करते हैं। भारत सरकार 'प्रवासी भारतीय दिवस' और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को विदेश नीति का हिस्सा बनाती है। प्रवासी समुदाय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष को समर्थन देते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए। भारतीय प्रवासी, भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में उभरे हैं। उनकी भागीदारी भारत की विदेश नीति को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावशाली और समावेशी बनाती है। प्रवासी भारतीयों को निवेश और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया गया (कामथ, पी.एम. 2014)।

भारत–अमेरिका के सम्बन्धों में एक नया आयाम

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति के मामले में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ संबंधों में आया है। आज भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी सामरिक साझेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा वित्तीय साझेदार बन गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार व निवेश लगभग 170 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इसमें सौ अरब डॉलर से भी ज्यादा का तो हथियारों का ही सौदा है। व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हित हैं। भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक

भागीदार बनकर सामने आया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा है जो आने वाले समय में और मजबूती प्रदान करेगा।

भारत और अमेरिकी के बीच नए संबंधों की शुरूवात हो चुकी है जो दोनों के भूराजनीति और वैश्विक रणनीतियों के लिए महत्व पूर्ण है। भारत और अमेरिकी दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते संबंधों को 21 वीं शताब्दी की एक महान मित्रता के रूप में देखा जा सकता है। यह मित्रता और साझेदारी अमेरिका में बढ़ती भारत की सॉफ्ट पॉवर के रूप में और भी मजबूत हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने और शांतिपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा देने का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश और रक्षा सचिवों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच 22 मंत्रिस्तरीय वार्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख संवाद व्यवस्था है। दोनों देशों के मध्य 22 वार्ता के माध्यम से रक्षा और सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया गया है । दोनों देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और फरवरी 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा सहित उच्च स्तरीय आदान–प्रदान की विशेषता रही है और कई मायनों में यह यादगार रहा तथा अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के मध्य कुछ आवश्यक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

जहां तक बात पड़ोस से इतर सुदूर पश्चिम, पश्चिम एशिया, ग्लोबल साउथ की बात है तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि साझेदारी सभी से, गठबंधन किसी से नहीं।' रूस–यूक्रेन युद्ध में मोदी सरकार की यह नीति का दुनिया ने दीदार कर लिया। अमेरिका और यूरोप के साथ बढ़ती साझेदारी के बावजूद भारत ने रूस से दूरी बनाने का दबाव स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भारत ने हर मंच पर खुलकर घोषणा की कि पश्चिम यह सोचना बंद कर दे कि उसका सुख–दुख दुनिया के सुख–दुख हैं (सुब्रमण्यम, एन. (2013)।

निष्कर्ष

2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और इसके साथ ही भारतीय विदेश नीति को एक नई ऊँचाई प्रदान करने का प्रयास किया है तथा वैश्विक जगत में भारत की पहचान को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा व सैन्य आत्मनिर्भरता को मुख्य प्राथमिकता दी गयी है। भारत एशिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र है, ऐसे में वैश्विक देशों की नजरें भारत की ओर लगी हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य भारत को समग्र क्षेत्र में आत्मनिर्भर और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप भारत आने वाले समय में एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत न केवल दक्षिण एशिया में अपितु वैश्विक जगत में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनायी है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ 'एक्ट ईस्ट नीति' के तहत अपने राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर है।

मोदी सरकार की विदेश नीति ने अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाकर अपने नेतृत्व को दिखा दिया है कि वह हर हाल में भारत की प्रतिष्ठा को ऊँचाईयों तक ले जाएँगें । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बहुआयामी और कूटनीतिक रूप से सक्रिय रही है। भारत ने न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। भारतीय प्रवासी के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए गए। इसके अलावा, रक्षा, आर्थिक विकास और सामरिक संतुलन के क्षेत्रों में भी कई महत्वपूर्ण पहलें की गईं। आज भी हम देखते हैं कि भारत लगभग साठ प्रतिशत सैन्य सामग्री रूस से आयातित करता है, परंतु आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर सैन्य व सुरक्षा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बन जाएगा आने वाले समय में ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है। हालांकि चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान के साथ स्थायी समाधान न होने जैसी चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं जो की वैश्विक कूटनीति के लिहाज से अच्छा नही माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत को एक सशक्त और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

संदर्भ–सूची (References)

- एंड्रयू, स्मॉल (2015), द चाइना पाकिस्तान एक्सिस: एशियाज न्यू जियोपॉलिटिक्स, अमेरिका: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 71–103।
- चेरियन, जे. (2017), गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक साझेदारी तक फ्रंटलाइन, 34 (17): 90–96।
- गांगुली, सुमित, (2018), भारत की विदेश नीतिरू पुनर्लोकन एवं संभावनाएँ, नोएडा: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया: 241।
- गांगुली, सुमित (2016), एंगेजिंग द वर्ल्ड: 1947 से भारत की विदेश नीति। दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस: 129।
- घोष, पीयू (2017), इंटरनेशनल रिलेशंस, दिल्ली फाइन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड 56।
- हैदर, सुहासिनी (2020), इस वर्ष भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं? द हिंदू, 27 दिसंबर 2020।
- हर्ष, वी. पंत (2016), भारतीय विदेश नीति एक अवलोकन, भारत ओरिएंटल ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड: 34–35।
- कामथ, पी.एम. (2014), भारत एक उभरती हुई प्रमुख शक्ति के रूप मेंरू विदेश नीति महत्व क्षेत्र, दिल्ली विश्व मामलों की भारतीय परिषद: 107।
- सुब्रमण्यम, एन. (2013), भारत की विदेश नीतिरू चौनिंग परिदृश्य, दिल्ली: अकादमिक प्रकाशन: 79।